वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर स्कीम को लागू करना चाहती है ? अगर हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ? अगर नहीं लागू करना चाहती है तो सरकार के पास कौन सी रीअल रेमिडी है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम तो, अध्यक्ष जी, हारवेस्ट की योजना को लागू करना चाहते हैं जिससे कि वह लवणता, जो हमारी जमीन में आ रही है और भूमिगत जल में आ रही है, उसको रोका जा सके। उसके लिए विभिन्न प्रकार के जो परीक्षण किए गए हैं, उनमें जो सर्वाधिक सफल परीक्षण होगा उसको लागू करके हम इस समस्या पर काबू पा सकेंगे ।

MR. CHAIRMAN : Question No. 65.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA : Mr. Chairman, Sir, I haver been unable to catch your attention during Question Hour since yesterday. I think it is better to withdraw from the House during Question Hour.

(At this stage the hon. Member left the Chamber)

कृषि पर आधारित प्रसंस्करण एककों का स्थापित किया जाना

*65. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कृषि पर आधारित प्रसंस्करण एकक स्थापित करने पर विशेष जोर दे रही है, यदि हां, तो देश में इस तरह के कितने एकक अब तक स्थापित किए गए हैं;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने-कितने एकक स्थापित करने का विचार है; और

(ग) हरियाणा में किन-किन औद्योगिक स्थलों पर ऐसे एकक स्थापित किए जा रहे हैं और उनमें किए जाने वाले संभावित पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN) : (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) to (c) Yes Sir, Statistics regarding all processing units are not maintained Centrally. However, information pertaining to the number of rice mills, or flour mills, fruit and vegetable processing units and sweetened aerated water manufacturing units registered under FPO and fish, processing units, statewise are given in Annexure-I (See below). Besides, as per census conducted by office of DC (SSI), there were 96123 Small Scale units manufacturing food products, in the country as on 31-3-1988.

Twenty eight proposals of agro-based units received from State Governments are under consideration of National Cooperative Development Corporation. State-wise details including Haryana have been given in Annexure-II *(See below).*

Nine letters of intent for setting up beer units one for alcohol unit, three 100% EOUs for fruit & vegetable processing, one for cereal processing and one for consumer goods have recently been approved for being set up in Haryana at Maunipur, Gurgaon, Faridabad, Mohindergarh, Hi-ssar, Jind, Bhiwani, Gannar and Manesar

Annexure-I

(I) *Number of fruit & vegetable processing units and sweetend aerated waters units (on 31-1-1992)*

Sl. No.	Name of State	F & VP units	SAW units
1	2	3	4
1	Andhra Pradesh	201	—
2	Assam	19	—
3	Bihar	43	10

1	2	3	4
4	Gujarat	171	52
5	Haryana	115	17
6	Himachal Pradesh	70	1
7	Jammu & Kashmir	68	6
8	Karnataka	176	38
9	Kerala	259	24
10	Madhya Pradesh	82	27
11	Maharashtra	506	85
12	Manipur	11	1
13	Meghalaya	7	1
14	Nagaland	4	—
15	Orissa	17	44
16	Punjab	158	9
17	Rajasthan	78	24
18	Sikkim	2	—
19	Tamil Nadu	314	35
20	Tripura	3	—
21	Uttar Pradesh	379	39
22	West Bengal	214	23
23	Andaman & Nicobar Island	1	—
24	Arunachal Pradesh	2	—
25	Chandigarh	24	—
26	Dadra & Nagar Haveli	5	2
27	Delhi	151	16
28	Goa	131	80
29	Mizoram	2	—
30	Pondicherry	9	7
	Total:	3222	577

(2) *Fish Processing Units (as on 31-12-1991)*

Name of State	No. of Units
Kerala	108
Karnataka	19
Lakshdweep	—
Tamil Nadu	31
Maharashtra	41
Gujarat	28
Goa	5
Andhra Pradesh	26
West Bengal	30
Orissa	15
TOTAL :	299

In addition, there are 131 ice making units and 330 cold storages.

(3) *Number of Rice Mills as on 1-1-1992*

Sl. No.	State/U.Ts.	Hullers	Shellers	Hullers cum Shellers	Modern/ Modernised Rice Mills	Total
1	Andhra Pradesh	4609	1776	2364	12995	21744
2	Assam	305	14	1871	418	2608
3	Bihar	4749	63	9	51	4872
4	Gujarat	1890	159	67	1045	3161
5	Haryana	807	—	—	990	1797
6	Himachal Pradesh	890	1	1	222	1115
7	Jammu & Kashmir	—	—	—	—	—
8	Karnataka	9131	462	1103	3674	14370
9	Kerala	13413	2	13	2668	16096
10	Manipur	71	—	97	1	169
11	Maharashtra	6191	99	472	2515	9277
12	Madhya Pradesh	3114	239	227	94	3674
13	Meghalaya	85	—	8	—	93
14	Nagaland	—	—	—	—	—
15	Orissa	6398	125	281	552	7364
16	Punjab	4416	442	—	1965	6823
17	Rajasthan	152	2	6	193	353
18	Sikkim	17	—	—	—	17
19	Tamil Nadu	13292	144	1530	3262	18228
20	Tripura	689	5	8	1	703
21	Uttar Pradesh	5707	562	150	1215	7634
22	West Bengal	9404	2	71	980	10457
23	Chandigarh	4	—	—	27	31
24	Delhi	3	—	—	31	34
25	Pondicherry	179	—	8	33	220
26	Andaman & Nicobar Island	116	—	—	—	116
27	Dadra & Nagar Haveli	8	1	—	—	6
28	Lakshadweep	—	—	—	—	—
29	Goa	675	—	5	37	717
30	Mizoram	—	—	—	—	—
31	Arunachal Pradesh	—	—	—	—	—
	Total	86315	4098	8300	32969	131682

(4) *Total Number of Roller Flour Mills as an 1-1-92*

Sl. No.	Name of State/U.Ts.	Total no. of Flour Mills
1	2	3
1	Andhra Pradesh	56
2	Assam	41
3	Bihar	44
4	Chandigarh	2
5	Delhi	17
6	Gujarat	27
7	Haryana	16
8	Himachal Pradesh	12
9	Jammu & Kashmir	18

1	2	3
10	Karnataka	54
11	Kerala	27
12	Madhya Pradesh	25
13	Maharashtra	45
14	Manipur	1
15	Orissa	21
16	Punjab	16
17	Pondicherry	2
18	Rajasthan	5
19	Tamil Nadu	53
20	Uttar Pradesh	70
21	West Bengal	27
22	Sikkim	1
23	Goa	1
24	Tripura	2
	TOTAL :	583

Annexnre-II

State-wise Position of Agro based Industries proposed to be set up during Current Financial year under NCDC Schemes

SI. No.	Name of the State	Proposal received during 1992-93	Proposal Under consider-ation	Type of Unit
1	Andhra Pradesh	2	1	Oil Mill & Soapery, and Integrated Oil Complex.
2	Haryana	2	2	Ginning & Pressing under Corporation Sponsored Scheme.
3	Kerala	1	1	Spinning Mill Handloom Weavers.
4	Maharashtra	10	11	F & V Processing Unit, Modernisation and expansion of sugar Mill, Estt. of Distillery, Particle board Units, Spinning Mill Growers and Handloom Weavers.
5	Manipur	1	—	F&V Processing Unit.
6	Orissa	1	2	Tamarind powdering Unit & Modernisation / Expansion of Sugar Mill.
7	Karnataka	—	1	Modernisation / Expansion of Sugar Mill.
8	Punjab	—	2	Distillery.
9	Rajasthan	2	2	Mustard Oil Mill, and Ginning & Processing.
10	Tamil Nadu	—	2	Distillery.
11	Uttar Pradesh	2	2	Modernisation/Expansion Cost escalatioin of Sugar Mill & Vanaspati Oil Mill.
12	West Bengal	2	2	Weavers Spinning Mills.
	TOTAL :	23	28	

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : चेयरमैन साहब, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और श्री उपेन्द्र जी का भी धन्यवाद करता हूं कि वे गैर-हाजिर हो गए और इसलिए मुझे चांस मिल गया ।

मैं एग्रीकल्चर मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि यह किसान विरोधी जो सरकार की पालिसी है, यह कब तक चलेगी ? एक तरफ तो हमें सोयाबीन बीजने के लिए उकसाया जा रहा है, सूरजमुखी की काश्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और दूसरी तरफ कोई भी ऐसा यूनिट इनका तेल निकालने के लिए सरकार नहीं बना रही है जिससे कि उनको अच्छी उजरत मिल सके। सरकार ने न सिर्फ गेहूं का ही इम्पोर्ट किया, उसके बाद अखबार में मैं यह खबर पढ़ रहा था कि इन्होंने सोया आयल बाहर से 50 लाख टन इम्पोर्ट किया और पाम आयल मलेशिया से इम्पोर्ट किया जिससे कि सोयाबीन की कीमतें भी गिर गईं और अकेले मध्य प्रदेश में 300 करोड़ रुपए का घाटा हुआ किसानों को । मैं जानना चाहता हूं कि जब आप सोयाबीन और सनफ्लावर की काश्त करने के लिए किसानों को उकसाते हैं तो उनके लिए यूनिट आप क्यों नहीं लगाते ? हरियाणा, पंजाब के अंदर बड़ा एक प्रोग्राम चल रहा है इन फसलों का, वहां पर आप तेल निकालने के लिए कारखाना क्यों नहीं लगाते ? किसानों को सबसीडी आप क्यों नहीं देते ? यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा ताकि किसानों को उनकी उजरत मिल सके और वे कौड़ियों के दाम अपने माल को न बेच सकें ।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : माननीय सभापति जी, लाठर साहब का दृष्टिकोण ज्यादा तेज लगता है । ऐसी बात नहीं है कि किसान विरोधी काम किया जाए । उत्पादन बढ़ाने के लिए, तेल के लिए, खाद्य तेल के लिए जैसा भी उपक्रम किया गया है और जो किसान ने किया है, उसकी सराहना करना तो हमारा काम है । जैसे कि पौने ग्यारह मीलियन से पौने उन्नीस मिलियन तक तो तेल का उत्पादन हुआ है । यह ठीक बात है कि अभी तक इस तरीके से जैसे पिछले सालों से सूरजमुखी और सोयाबीन का उत्पादन हुआ, सोयाबीन का तो काम मध्य-प्रदेश में ज्यादा है । पहली बार हरियाणा में और पंजाब में सनफ्लावर की खेती हुई है, उसके लिए गवर्नमेन्ट ने एक किस्म से एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्री इन दि मिनिस्ट्री आफ इण्डस्ट्री 1990 में और एक हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने 1988 में, दो नई मिनिस्ट्री बनाईं इस काम के लिए । तो जरूरी है कि उनके उत्पादन को किस तरीके से हम ठीक ढंग से लगा सकें, किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकें, उसके लिए हम उपक्रम करेंगे और अवश्य बनाएंगे । प्राइवेट इंडस्ट्री को भी लगाने की बात कर देंगे, को-आपरेटिव के लिए भी हम मदद करना चाहेंगे और यह आवश्यक है और इस बात के लिए हम प्रयत्नशील हैं और लगाएंगे इस बात के लिए और प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है । दूसरी बात आपने सोयाबीन के मुताल्लिक कही है । तो आप अन्दाजा कर सकते हैं कि हम इस बार तकरीबन-तकरीबन ठीक हिसाब से चल रहे हैं और खाद्य तेलों का उत्पादन भी ठीक है । मलेशिया के साथ जरूर कामर्स मिनिस्ट्री ने कुछ बनाया है । पिछले साल का कुछ कांट्रेक्ट हुआ है । लेकिन वह तब मंगाया जाएगा जब उसकी आवश्यकता होगी । पचास हजार टन जो सोया आया है वह हमने खरीदा नहीं है, वह कुछ और ही तरीके से आया है। वह बेचा नहीं जाएगा जब तक कि कोई आवश्यकता नहीं होगी । मार्केट में वह तभी लाया जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है उस बात के लिए । दूसरी बात यह है कि आप सोयाबीन की बात करते हैं। आपको ज्ञात होगा कि दो किस्म के भाव होते हैं । एक तो वह भाव होता है जब उसकी बहुतायत ज्यादा होती है तो भाव गिर जाते हैं । दूसरे, जब कम होता है तो भाव अनाप-सनाप बढ़ जाते हैं । दोनों भावों के बीच में एक ऐसा संतुलित भाव होता है जिसको व्यवहारिक कहते हैं और उसके लिए हमने किसान का जो पैसा देना है, आप तारीफ करेंगे इस बात की कि पिछले साल हमने 80 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी सोयाबीन के लिए की है, जिससे कभी भी कुछ भी हो फिर भी किसान को उससे नीचे नहीं बेचना पड़े ।

श्री अजीत जोगी : महोदय, सोयाबीन का पैसा मध्य प्रदेश के किसानों को बिल्कुल नहीं मिला है । उन्हें 600 रुपये क्विंटल बेचना

पड़ा जब 900 रुपये का भाव था । 300 रुपये क्विंटल का घाटा हुआ . . . (व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ : नहीं, यह घाटा नहीं है । जो भाव . . . **(व्यवधान)**

एक सम्मानित सदस्य : सर, मध्य प्रदेश सोयाबीन का प्रदेश माना जाता है । . . . . **(व्यवधान)**

SHRI MOHINDER SINGH LATHER: Sir, I may be permitted to put my supplementary.

MR. CHAIRMAN : Please, after the second supplementary.

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : मैं कृषि मंत्री जी का इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो लोग, जो काश्तकार अंगूर पैदा करते हैं, क्योंकि अंगूरों की खेती के लिए सरकार ने ही उनको प्रोत्साहित किया था। अब पंजाब व हरियाणा में बहुत अंगूर पैदा हो रहा है । लेकिन यह बदकिस्मती की बात है कि जब फसल आती है तो उसको एक रुपए किलो के भाव में भी कोई लेने को तैयार नहीं होता। आपने कोई वाइनरी हरियाणा, पंजाब में नहीं लगाई है । मुझे फ्रांस जाने का मौका मिला था और चेयरमैन सर, वहां यह वाइनरी विलेज काटेज इण्डस्ट्री की तरह है । हर गांव के अंदर वाइन निकाली जाती है। मैं समझता हूं कि अगर आप यह वाइनरी हरियाणा, पंजाब के अंदर भी सेट-अप करें तो उससे न सिर्फ किसानों को उसकी फसल के पैसे मिलेंगे, बल्कि यह जो दुष्ट शराब पी जाती है और जिससे काफी नुकसान होता है तथा नकली शराब से लोग मरते हैं तो यह जो वाइन है और यह वाइन शराब नहीं है तथा यह बहुत माइल्ड है और सेहत के लिए अच्छी है । तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या आप वाइनरी को विलेज काटेज इंडस्ट्री बनाएंगे, ताकि यह प्रोसेसिंग का काम भी करे और किसानों को उनके पैसे भी मिलें ?

SHRI PRAMOD MAHAJAN : You cannot advertise liquor in the House. That is all.

श्री बलराम जाखड़ : सभापति महोदय, अंगूर के विषय में जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह शत-प्रतिशत सही है । मुझे तो इस बात का पता है कि सबसे पहले पंजाब में सरदार प्रताप सिंह कैरो जो चीफ मिनिस्टर थे, वह पहले आदमी थे जिन्होंने अंगूर की खेती की थी । लेकिन सवाल इतना ही पैदा हो जाता है कि जिस तरीके से किसान को एक ही तरफ से लाभ मिलता है तो वह उसी तरफ बढ़ा चला जाता है । हमें उस चीज को सीमाबद्ध करके उसको प्लानिंग और आयोजन करना पड़ेगा कि कितनी आवश्यकता है व कितना उत्पादन करना है । यह सब प्लानिंग करनी पड़ेगी । जब हमने 1961 में शुरू किया था, एक पहला एकड़ अंगूर का मैंने लगाया था और आज 35 हजार एकड़ में अंगूर है और सही बात है कि अंगूर बिकता नहीं है और उसी के लिए मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि इसीलिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बनाने का विचार है । जैसे पेरिशेबिल प्रोडक्ट्स हैं, सभी तबाह हो जाती हैं, 25 प्रतिशत वैसे तबाह हो जाती है, उनका उपयोग होता नहीं है । किसान को उसका पैसा मिलता नहीं है, न उसकी वेल्यू एडीशन होती है, न उसको हम पूरा रख सकते हैं । तो यह सारी बातें देखते हुए एक ही तरीका है कि हम एग्रो इंडस्ट्री विलेजिज में लगाएं । सही कहते हैं कि इस तरह की यह लिक्यर नहीं है, जिसकी आप बात करते हैं । तो उस लिक्यर को छोड़ करके कुछ ऐसा उत्पादन करें । मैंने पंजाब सरकार को भी कहा है, हरियाणा की सरकार को कहूंगा कि इस तरीके से करें कि लोग आकर्षण में आएं और हम चेंज करना चाहते हैं। हम उस वेराइटी को भी चेंज करना चाहते हैं। जो लोगों ने पूना में कर रखी है । पूना में मैंने फैक्टरी लगवाई थी । उसको सारी की सारी सेम्पल बनाकर फ्रांस में भेजते हैं, जो यूरोप में कम्पटीशन में सेकंड आई है । हम उसको बाहर भेज सकते हैं । लेकिन कुछ ऐसा उपयोग अवश्य होना चाहिए जिससे कि किसानों को पैसा मिल सके । फ्रूट्स में भी पैसा मिले . . . (व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : अंगूर का तो आ गया, उसकी बेटी का क्या करेंगे . . . **(व्यवधान)**

श्री बलराम जाखड़ : शुक्र है बेटा नहीं हुआ, बेटी है...(व्यवधान) मैं सारा बंदोबस्त इस हिसाब से करना चाहता हूं कि इन इंडस्ट्रीज पर जोर दिया जाए और इसीलिए यह मिनिस्ट्रियां बनाई गई हैं जिससे कि इस काम को हम बढ़ावा दे सकें और आने वाले जमाने में एक नया डाईवर्सिफिकेशन करें। वरना किसान के पास पैसा नहीं जाता है। उसकी जेब में पैसा जाना जरूरी है ।

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Centenary celebration of Tehugu play "KANYASULKAM"

*63. SHRI P. UPENDRA : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the centenary of a great social play in Telugu "Kanyasulkam" by the immortal poet Gurujada Appa Rao was observed recently in Andhra Pradesh; and

(b) if so, whether the Central Government have recognised the event and what action has been taken in this respect ?

THE MINISTER OF HUMAN RIVSOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) The Central Government celebrates the birth centenaries and jubilee years of outstanding personalities and national events like Quit India Movement. There is no procedure by which Government of India can 'recognise* any event.

Import of wheat

*66. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: DR. NAUNIHAL SINGH :

Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) what is the purchase rate and total cost of imported wheat;

(b) whether it is a fact that wheat could have been procurred internally at a cheaper rate even by providing remunerative prices to the farmers of the country; and

(c) if so, the reasons for not procuring Wheat internally ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI) :

(a) The FOB cost of wheat for whichcontracts have been signed is as under:

Country of origin	Quantity (in lakh tonnes)	FOB cost (in US$ PMT)	
Canada	10.05	147.78	(Average)
Australia	5.00	137.50	
Australia . . .	5.00	135.00	
U.S.A.	9.85	110.50	Oct-Dec.'92 shipment
		112.50	Jan-March'93 shipment

The total CIF cost of 29.90 lakh tonnes of wheat being imported from Canada, Australia and U.S.A. is estimated to be US $ 497.94 million or Rs. 1294 crores. This includes ocean freight and insurance charges. Foreign exchange outgo on ocean freight will get reduced to the extent Indian ships are used.

(b) and (c) The procurement price of wheat of Rs. 280/- per quintal (comprising of the minimum support price of Rs. 250/-, Central incentive bonus of Rs. 25/- and State bonus of Rs. 5/- per quintal paid in Punjab, Haryana and Rajasthan) paid to the farmers for procurement of wheat during the current 1992-93 rabi